भूमि और जल की समस्याएं दूर होंगी

बैठक

- आईआईडीसी ने कंपनियों को दिया आश्वासन
- दस परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी में पंप्ड स्टोरेज पावर (पीएसपी) परियोजनाओं के लिए भूमि और जल आवंटन की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में कंपनियों को यह आश्वासन दिया गया। राज्य सरकार ने 10 पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें ग्रीनको समूह, टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी, एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस, अवादा वॉटर बैटरी प्राइवेट लिमिटेड, झरिया प्राइवेट लिमिटेड, अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टीएचडीसी शामिल हैं। इनमें से अधिकांश प्रस्ताव सोन नदी पर आधारित परियोजनाओं से संबंधित हैं।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने परियोजना डवलपर्स को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार भूमि से संबंधित मामलों का समयबद्ध समाधान के लिए काम कर रही है। राजस्व, वन व अन्य संबंधित विभागों के बीच प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे भूमि के कागजातों में स्पष्टता सुनिश्चित हो सके और परियोजना समय-सीमा को प्रभावित करने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके।

आईआईडीसी ने विभागों को निर्देश दिया कि अन्य राज्यों से होकर प्रवाहित होने वाली नदियों में उत्तर प्रदेश के हिस्से के अनुरूप जल पुनर्भरण से जुड़े सभी मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जल उपलब्धता और परियोजना आवश्यकताओं का आकलन किया जा चुका है, इसमें वर्तमान मांगों को शामिल किया गया है। अंतर्राज्यीय जल-वितरण व्यवस्थाओं का पालन किया जाना किए जाने की भी जानकारी दी गई।